reduced by collection charges not exceeding 12 per cent of the total collection within the State.

एल. पी. जी. एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों को खोलने में विलम्ब

*46. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री आस मोहम्मद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी क्षेत्र में एल.पी.जी. एजेंसी तथा पेट्रोल पम्प स्थापित करने में एक से दो वर्ष का समय लग जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) सामान्य परिस्थितियों में किसी खुदरा बिक्री डीलरशिप अथवा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आशय पत्र जारी किए जाने की तिथि से लगभग 6 से 8 माह के समय में चालू किया जा सकता है। परन्तु, कई मामलों में निम्नलिखित कारणों से इन्हें चालू करने में विलम्ब हो जाता है :

(1) विशेषकर महानगरों में उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होना/भूमि अर्जन में विलम्ब ।

(2) आशय पत्र धारकों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयां ।

(3) अनापत्ति प्रमाणपत्र/सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब ।

(4) डीलरों के चयन के विरुद्ध दायर किए गए न्यायिक मामले ।

(ग) डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शीघ्र चालू करने के लिए किए गए उपाय निम्नवत हैं :—

(1) राज्य/संघ राज्य सरकारों से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के अनुरोध पर विकास के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनुसूचित जाति / जनजाति आबंटितियों के मामले में जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, तेल कंपनियों को संग्रह धनराशि योजना के अंतर्गत शीघ्र निजी भूमि का अर्जन करने की सलाह दी गई है ।

(3) विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के संबंध में तेल कम्पनियों द्वारा की गई प्रगति की तिमाही समीक्षा की जाती है।

(4) डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू किए जाने की प्रगति की समीक्षा करने और शीघ्रातिशीघ्र उन्हें चालू करने के लिए प्रत्येक कंपनी में एक निगरानी प्रकोष्ठ का सृजन भी किया गया है ।

(5) तेल कम्पनियों को, विभिन्न अनुमोदनों/अनापत्तियों आदि की प्राप्ति और बैंक ऋणों आदि की व्यवस्था में आबंटितियों को सुविधा देने और सहायता करने के अनुदेश दिए गए हैं।

Allotment of New LPG Connections

*47. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have set any targets to provide new LPG connections in the country during 1994-95;

(b) if so, the details thereof, and

(c) what effective measures Government propose to take to achieve the said targets?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (c) During the year 1994-95, a target to enroll 20 lakh new LPG customers has been fixed. Oil marketing companies have already achieved the target by end February,, 1995.

ए. टी. एण्ड टी. और टाटा टेलीकाम के मध्य समझौता

*48. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए. टी. एण्ड टी. और टाटा टेलीकाम के मध्य कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) विवरण, सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मैसर्स ए. टी. एण्ट टी. और टाटा टेलीकाम के बीच हुए समझौते का विवरण

मैसर्स ए० टी० एण्ड टी० तथा टाटा टेलीकाम ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्विचन उपस्कर तथा डिजिटल संचारण उपस्कर के विनिर्माण के लिए मैसर्ज ए. टी. एण्ड टी. स्विचिंग सिस्टम्ज इंडिया प्रा. लि. तथा मैसर्ज ट्रांस इंडिया नेटवर्क सिस्टम्ज प्रा. लि. नाम से संयुक्त उद्यम की दो परियोजनायें स्थापित की हैं। इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. ए. टी. एण्ड टी. स्विचिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड :

विनिर्माण की मद :	डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर
उत्पादन क्षमता :	प्रति वर्ष 7.5 लाख लाइनें
प्रस्तावित इक्विटी-निवेश :	50 करोड़ रुपए
प्रस्तावित विदेशी इक्विटी :	255 करोड़ रुपए (51 प्रतिशत)
स्थान :	बेंगलूर, कर्नाटक
स्थिति :	उत्पादनरत

2. ट्रांस इंडिया नेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड :

विनिर्माण की मद :	डिजिटल नेटवर्क एक्सेस प्रणाली
उत्पादन क्षमता :	प्रति वर्ष 1000 प्रणालियां
प्रस्तावित इक्विटी निवेश :	7.15 करोड़ रु०
प्रस्तावित विदेशी इक्विटी :	3.57 करोड़ (50 प्रतिशत)
स्थान :	गांधी नगर, गुजरात
स्थिति :	उत्पादनरत।

Indo-Pak discussions on Kashmir

*49. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) on what consideration, Government are announcing that India is ready to discuss Kashmir issue bilaterally under the Simla Agreement; and

(b) what type of discussions Government want with Pakistan?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Simla Agreement provides the appropriate framework for settling all differences with Pakistan including those related to Jammu and Kashmir. Government are committed to resolving issues pertaining to bilateral relations with Pakistan peacefully and through a process of bilateral negotiations as stipu-